Bonus to L.I.C. Employees

2332. SHRI BIRENDRA PRASAD: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the LIC employees used to get bonus but the same was stopped during emergency; and

(b) if so, whether Government propose to pay bonus to them?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H M. PATEL): (a) and (b) The Class III and Class IV employees of LIC as per the settlements of 1974 (current from 1-4-1973 to 31-3-1977) were to be paid bonus without any ceiling at the rate of 15 per cent of annual salary. They had been paid bonus for two years *viz.* 1973-74 and 1974-75.

2 Following amendments to the Payment of Bonus Act 1965 through issue of an Ordinance in September 1975, Government decided that the employees of the non-competing public sector employees including Banks, L.I.C. and G.I.C. may be paid an *ex-gratia* amount beginning with the accounting year 1974/1974-75. The amount of *ex-gratia* was to range from zero to 10 per cent depending upon the wage level, financial circumstances and other relevant factors in the industry concerned.

3. It was however not possible to follow the guidelines in respect of LIC employees as there was a subsisting settlement between the Corporation and its employees for payment of bonus at the rate of 15 per cent of annual salary without any ceiling. To bring the employees on a par with those of the GIC and nationalised banks the provisions of the 1974 settlements so far as they pertained to payment of bonus was annulled by the Life Insurance Corporation (Modification of Settlements) Act, 1976 in March, 1976 which came into force with effect from 1-4-1975.

4. Although it had been decided to pay to eligible employees *ex-gratia* amount for the year 1975-76 at 4 per cent of annual salary, it could not be disbursed to them due to their refusal to take payment.

5. The validity of the L.I.C. (Modification of Settlements) Act, 1976 has been challenged in the Supreme Court by two unions of the LIC Class III and Class IV employees. As the hearing of the case is already going on in the Supreme Court the Government in the circumstances propose to wait for its outcome.

आलू का निर्यात

2333. **श्री राम लाल राही**: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरवरी, 1977 में आलू के निर्यात पर रोक लगा दी थी जिसके परिणामस्वरूप आलू उत्पादकों में निराशा व्याप्त है और आलू के मूल्यों में गिरावट आ रही है ;

(ख) यदि हां तो सरकार का विचार आलू के निर्यात पर लगी रोक कब तक उठाने का है; और

(ग) आलू के निर्यात से वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) फरवरी, 1977 में आलू के निर्यातों पर इस बात को ध्यान में रखते हुये रोक लगाई गई थी कि आलू की घरेलू कीमतें ऊपर चढ़ रही थीं और फसल की सम्भावना अच्छी नहीं थी। निर्यातों पर रोक लगने के बाद भी कीमतों में ऊंच रुख बना रहा और थोक कीमतों का मासिक सूचकांक रोक लगने के समय प्रचलित कीमतों की अपेक्षा रोक

लगाने के बाद की अवधि में आमतौर पर ऊंचा रहा। इन बातों को देखते हुये यह कहना सही नहीं होगा कि फरवरी, 1977 में आलू के निर्यात पर रोक लगाने के फलस्वरूप कीमतों में गिरावट का रुख रहा तथा उससे आलू उगाने वालों को निराशा पैदा हुई।

(ख) आलू के निर्यातों पर रोक हटाने के प्रश्न पर फसल की सम्भावना और कीमतों के रुख को ध्यान में रखते हुये उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

(ग) सम्बन्धित अवधि में मूल्य की दृष्टि से आलू के निर्यात निम्नांकन प्रकार रहे :—

वर्ष	मूल्य (लाख रुपए में)
1974–75	68.66
1975–76	348.17
1976–77	585.15

Decision to export smaller quantity of Sugar

2334. SHRI S. R DAMANI: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether Government have decided to allow export of much smaller quantities of sugar this year; and

(b) if so, the details and reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) and (b). In July, 1977 the Government had decided that during the financial year 1977-78, out of the production during the sugar year 1976-77, exports should be allowed to meet the existing firm commitments in a manner so as to minimise the losses. The total commitments to be thus fulfilled were to the extent of 1.45,000 tonnes out of which 1,20,000 was for Iran and 25,000 tonnes for EEC. During the current financial year, STC has exported 0.45 lakh tonnes valued at Rs. 10.43 crores so far, out of the quantities of sugar contracted for export during 1976-77.

बहुमूल्य जीवन रक्षक औषधियों की तस्करी

2336. **श्री बृजभूषण तिवारी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अक्तूबर, 1977 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि प्रेडिनीसोलोन, टेट्रासाइक्लीन और एनल्जीन जैसी बहुमूल्य जीवन रक्षक औषधियों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है, और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल): (क) जी हां। इस आशय का एक समाचार था। परन्तु सरकार को मिली रिपोर्टों से देश में इन औषधियों के हाल ही में बड़े पैमाने पर चोरी-छिपे लाये जाने का संकेत नहीं मिलता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है। फिर भी स्थिति पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखी जा रही है।